राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 14 जून 2026
वर्ष 14, अंक 65, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने किया स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण...03

बिल्कुल बर्दाश्त नहीं...ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर हमले..04

असम में 18+ वालों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, हिमंत बिस्वा सरमा सरकार का बड़ा फैसला

- असम की हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने संदिग्ध प्रवासियों के आधार कार्ड नहीं बनाए जाने का फैसला लिया है
- मुख्यमंत्री ने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने अवैध प्रवासियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. हिमंत कैबिनेट ने संदिग्ध प्रवासियों के आधार कार्ड नहीं बनाए जाने का फैसला लिया है. कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अब 18 वर्ष से अधिक आयु वाले संदिग्ध लोगों को यह कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ये फैसला अवैध प्रवासियों को राज्य में फैलने से रोकने के लिए किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा. इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाद में तय करेगी कि कोई आवेदक आधार कार्ड के लिए योग्य है या नहीं. उन्होंने कहा कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया उस चरण तक पहुंच गई है जहां लगभग सभी योग्य लोगों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में यह आंकड़ा 100 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है और ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है जिन्होंने ये अतिरिक्त आधार कार्ड हासिल किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड न बनवा सके.

अवैध प्रवासियों ने असम बनाया 'बफर स्टेट'

दरअसल, असम से सटे बांग्लादेश से अवैध तरीके से कई प्रवासियों का आवागमन सालों से होता रहा है जिससे राज्य के भीतर कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं. कई अवैध प्रवासी राज्य में अपना ठिकाना बना लेते है. इसी हालात को देखते हुए असम के सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया है।

जानें कब से लागू होगा आदेश

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि उनमें से कई लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पाबंदी 1 अप्रैल, 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगी. उस तारीख के बाद, इन समुदायों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।

हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले ही दिए थे संकेत

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने को लेकर बहुत सख्त रवैया अपनाएगी और असम में यह दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं होगा. पिछले साल, उन्होंने बताया था कि असम सरकार बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवासन को रोकने की कोशिशों के तहत वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही थी।

असम में आधार कार्ड का वितरण पहले ही अपने संतृप्ति बिंदु (सैचुरेशन प्वाइंट) पर पहुंच चुका है। सरकार ने सामाजिक संतुलन और समावेशिता का ध्यान रखते हुए चाय बागान श्रमिकों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फिलहाल इस नियम से छूट दी है, क्योंकि इन समुदायों के कई लोगों के पास अब भी आधार कार्ड नहीं हैं। लेकिन यह छूट भी हमेशा के लिए नहीं है।

विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी रियायत

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू होगा, लेकिन अत्यंत असाधारण मामलों में कुछ ढील दी जा सकती है। यदि 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति आधार के लिए आवेदन करता है, तो जिला उपायुक्त को उसकी पात्रता की गहन जांच करनी होगी। इसके बाद जिला प्रशासन को राज्य सरकार के पास एक विशेष प्रस्ताव भेजना होगा। राज्य सरकार ही अंतिम रूप से यह तय करेगी कि आवेदक इस दस्तावेज को पाने का हकदार है या नहीं।

अजमेरा ग्रुप के निवेशकों को वापस मिलेंगे 8.41 करोड़ रुपए, पीएमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला

- ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी
- बाद में पीड़ितों और वैध दावेदारों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से ईडी ने अदालत में संपत्तियां लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई

बेंगलुरु के अजमेरा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. विशेष PMLA अदालत ने 8.41 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां उनके वैध दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया है। ईडी की जांच में सामने आया था कि अजमेरा ग्रुप ने लोगों से अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन बाद में न तो वादा किया गया लाभ दिया और न ही मूल रकम लौटाई. जांच के दौरान यह भी पता चला कि निवेशकों का पैसा कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर कर उससे कई चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं. ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।

संपत्तियां लौटाने पर ईडी ने नहीं जताई आपत्ति

बाद में पीड़ितों और वैध दावेदारों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से ईडी ने अदालत में संपत्तियां लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. ईडी की सिफारिश पर विशेष अदालत ने 9 जून 2026 को आदेश जारी कर 8.41 करोड़ रुपए की अटैच संपत्तियां पीड़ितों और वैध दावेदारों को वापस करने की अनुमति दे दी. इसे निवेशकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अंतरिम कुर्की आदेश जारी

बता दें कि ईडी की जांच में पता चला कि भारी मात्रा में धन अजमेरा ग्रुप के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और उसी धन का उपयोग उनके नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. जांच के दौरान, ईडी ने एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें विभिन्न आरोपियों की कई चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया और बाद में विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई

अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश

धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वास्तविक दावेदारों को संपत्ति का मूलधन वापस दिलाने के उद्देश्य से पीएमएलए के तहत ईडी ने विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष कुर्क की गई संपत्ति को धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वास्तविक दावेदारों को सौंपने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई. ईडी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय ने 9 जून को एक आदेश पारित करते हुए धन शोधन अपराध के पीड़ितों और वैध दावेदारों को कुर्क की गई अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया है।

प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की दायर

» प्रॉपर्टी कुर्क करने के बाद, ईडी ने स्पेशल कोर्ट के सामने एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की है।

» ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन पेश किया, जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीड़ितों और वैध दावेदारों को सौंपने की भी बात कही गई।

» पीएमएलए कोर्ट ने आदेश दिया जिसके तहत कुर्क की गई अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के शिकार वैध दावेदारों और पीड़ितों को वापस करने का निर्देश दिया गया है।

2018 में दायर की थी एफआईआर

ईडी के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मकसद अपराध से हुई कमाई को वास्तविक और वैध दावेदारों या मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को वापस दिलाना है. ईडी ने अप्रैल 2018 में जयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. इसी मामले में बाद में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

संक्षिप्त ख़बरें

बीडीओ व सचिव की साठ गांठ से टेंडर प्रक्रिया में किया जा रहा बहुत घोटाला

निघासन खीरी ब्लॉक में बीडीओ और सचिव की मिलीभगत से टेंडर प्रक्रिया में किया जा रहा घोटाला,सिर्फ एक ही अखबार को दिए जा रहे टेंडर,बताया जा रहा है कि सचिव और बीडीओ के तलवे चाटने वाले और ब्लॉक में पैठ बनाने वाले एक ही अखबार को मिल रहा टेंडर, पुराने,नए कार्य के टेंडर प्रक्रिया में ब्लॉक के जिम्मेदार खेल रहे खेल,टेंडर में भी कमीशनखोरी करके बीडीओ,सचिव,कुछ हां हजूरी करने वाले पंचायत मित्र मनमाने ढंग से छपवा रहे टेंडर,निष्पक्ष जांच से टेंडर प्रक्रिया में भी मिलेंगी धांधली,ब्लॉक की गतिविधियों पर उठ रहे सवालिया निशान।

बवाना से औचंदी बार्डर तक बनेगा एलिवेटेड रोड

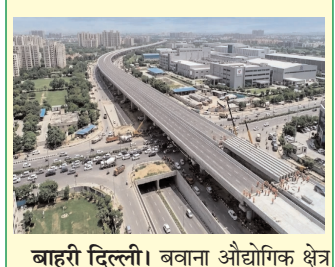

बाहरी दिल्ली। बवाना औद्योगिक क्षेत्र से लेकर औचंदी बार्डर तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने इस योजना पर काम करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए लगभग 3.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। कंपनी इस एलिवेटेड रोड के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करेगी, जिसमें यातायात सर्वेक्षण, प्रारंभिक डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आदि तैयार करने का काम भी शामिल होगा। यातायात जाम प्रभावित इस क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनने के बाद बवाना औद्योगिक क्षेत्र से लेकर हरियाणा तक आवाजाही आसान होगी। समय और ईंधन दोनों बचेंगे। बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर औचंदी बार्डर तक मार्ग पर यातायात जाम से राहत का प्लान बनाया जाना है।

जंग से महंगा हुआ तारकोल, मुश्किल में सड़क निर्माण... संसदीय समिति मंत्रालय से मांगेगी जवाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम एशिया संकट के भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर असर को लेकर संसदीय समिति ने सोमवार को बैठक बुलाई है. इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को बुलाया गया है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत में तारकोल (बिटुमेन) का संकट हो रहा है. इसके कारण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के काम में बाधा आ रही है. ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर मामलों की संसदीय समिति इस पर चर्चा करेगी. युद्ध के कारण वीजी-40 ग्रेड के तारकोल की कीमत करीब दोगुनी हो गई. जबकि सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 15 जुलाई तक लगभग छह लाख टन की अनुमानित जरूरत के मुकाबले इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है। भारत में सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है. इस कारण सड़क निर्माण के लक्ष्य पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. भारत वैकल्पिक आपूर्ति के रास्तों की तलाश कर रहा है।

बिटुमेन की कमी से हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी

रिपोर्ट के अनुसार रूस से तेल आयात होने की वजह से देश में कच्चे तेल की उपलब्धता ठीक-ठाक बनी हुई है, लेकिन इससे बिटुमेन की सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ है. रूस से आने वाला स्वीट क्रूड ऑयल भारतीय मौसम के लिए सही बिटुमेन ग्रेड नहीं बना सकता. रूसी तेल में सल्फर बहुत कम होता है, जिससे बिना खास प्रोसेसिंग के वीजी-10 या वीजी-30 जैसे कम ग्रेड के बिटुमेन बनते हैं। सूत्रों का कहना है कि वीजी-40 उस क्रूड ऑयल से बनता है जो हमें पश्चिम एशियाई देशों से मिलता है और ज्यादातर तैयार प्रोडक्ट भी इन्हीं देशों से होर्मुज स्ट्रेट के जरिए आयात किए जाते थे. इस लड़ाई से इस सप्लाई पर असर पड़ा है और इसका असर हाईवे के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन पर भी पड़ रहा है।

बिटुमेन की कमी ने बढ़ाई सरकार की चिंता

यह मुद्दा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (आईजीओएम) की पिछली मीटिंग में भी उठाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे जरूरी क्वालिटी के बिटुमेन की कमी ने अप्रैल में हाईवे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार को एक-चौथाई तक कम कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण, नगर निगम और राज्य की सड़कों के मामले में भी असर एक जैसा है. उनका कहना है कि कीमतें और बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम ज्यादा कीमत पर भी अपना काम पूरा करने के लिए बिटुमेन कैसे पाएं।

तुगलकाबाद अग्निकांडः छह लोगों को ग्रिल से साड़ी बांधकर नीचे उतारा तो छत के रास्ते 10 की बचाई जान

- पड़ोसियों ने साड़ी और दुपट्टों से लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा।
- बगल के मकानों की ग्रिल काटकर कई लोगों को बचाया गया।
- छत का ताला तोड़कर 16 लोगों की जान बचाई गई।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दक्षिणी दिल्ली। रात लगभग सवा दो बजे सामने के फ्लैट में रहने वाले सौरभ शर्मा को उनकी बेटी अंशु ने जगाया। आसपास बहुत शोर हो रहा था। उन्होंने उठकर देखा तो सामने के फ्लैट से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। फायर ब्रिगेड को फोन मिलाते हुए मदद के लिए नीचे उतरे। पास की रहने वाली रेनू मलिक समेत आसपास के कुछ लोग मकान के पीछे की ओर गए। कुछ आगे से बचाने के प्रयास किया जाने लगा। उनकी 16 वर्षीय बेटी अंशु ने अपने तीसरे तल की खिड़की से साड़ी दूसरे तल पर मदद के लिए पुकार रहे एक व्यक्ति पर फेंकी। व्यक्ति ने साड़ी को बरामदे की ग्रिल से बांधा और नीचे उतर आया। वे बताते हैं कि आसपास के अन्य लोगों ने भी साड़ी और दुपट्टे बरामदों पर फेंके। इस ओर फंसी चार-पांच महिलाओं ने भी इसी तरह नीचे उतरकर अपनी जान बचाई।

मकान में लगभग 24 लोग फंसे थे

मकान के पिछले हिस्से में बचाव कार्य का नेतृत्व करने वाली रेनू भाटिया ने बताया कि जब वे पहुंची तो पार्किंग में छह-सात बाइकें जल रही थीं। मकान में लगभग 24 लोग फंसे थे। हम लोग पीछे की गली में पहुंचे। भूतल पर निकलने के लिए कोई गेट नहीं है। पहली से पांचवें तल तक बरामदे तो थे, पर उन्हें ग्रिल लगाकर कवर किया गया था। सामने के मकान भी बिल्कुल सटे हुए हैं।

छह लोगों को पहले बगल की छत पर उतारा

उनके बरामदों से ग्रिल काटकर कुछ लोगों को निकाला गया। वहीं बगल के एक मकान की छत से भी लोग ऊपर पहुंचे। जल रही इमारत के छत वाले गेट पर अंदर से ताला था। जान बचाने के लिए कुछ लोग दरवाजे के पास जमा थे। अंदर से उन्हीं लोगों ने ताला तोड़ा। तीन बच्चियों समेत छह लोगों को पहले बगल की छत पर उतारा। फिर सीढ़ियों से नीचे ले आए। इस तरह लगभग 16 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आने से पहले छत पर रखी पानी की टंकी फोड़ दी गई, ताकि नीचे आग पर कुछ काबू पाया जा सके। वहीं पावर कट कराकर लोग बाल्टियों में पानी भर-भरकर पार्किंग एरिया में लगी आग बुझाने में जुटे रहे।

दिल्ली में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, थाईलैंड की 3 समेत 15 युवतियां मुक्त

- दक्षिणी दिल्ली के स्पा सेंटरों से 15 लड़कियां मुक्त कराई गईं।
- थाईलैंड की तीन लड़कियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे।
- पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत FIR दर्ज की।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दक्षिणी दिल्ली। कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में संचालित तीन स्पा सेंटर से पुलिस ने थाइलैंड की तीन समेत कुल 15 लड़कियों को मुक्त कराया। आरोप है थाइलैंड की लड़कियों का पासपोर्ट रख लिया गया था और उनसे जबरन जिस्मफरोशी कराई जा रही थी। मिशन मुक्ति फाउंडेशन व रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन ने इसकी शिकायत दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल से की। एसीपी डिफेंस कालोनी के नेतृत्व में टीम गठित हुई। 10 जून को कुछ पुलिसवालों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया।

पुष्टि होते ही टीम ने छापेमारी की। तीनों स्पा सेंटर से तीन थाइलैंड की लड़कियों के साथ ही उत्तर प्रदेश व हरियाणा की 12 लड़कियों को भी मुक्त कराया। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिकों तालिब, मंजू बिष्ट, गुड्डू कुमार व एक अज्ञात के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा तीन, चार व पांच के तहत एफआइआर दर्ज किया है। पीड़िताओं को बयान दर्ज कर उन्हें वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया है। वहीं आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

वोट चोरी, सरकार चोरी के बाद अब 'सीट चोरी', बीजेपी-चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने मुकाबला ही खत्म किया: राहुल गांधी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर सवाल उठाते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि 'वोट चोरी' और 'सरकार चोरी' के बाद अब बीजेपी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत ने 'सीट चोरी' के जरिये चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, ''वोट चोरी और 'सरकार चोरी' के बाद, अब बीजेपी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत ने 'सीट चोरी' के ज़रिये चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा किए थे। उन पर कोई मामला लंबित नहीं था। फिर भी, निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया।''

राहुल गांधी ने कहा, ''वहीं, झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने आवेदन में अपना नाम ही गलत लिखा और कई ज़रूरी जानकारी भी नहीं दी। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया।'' उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग वही था। उम्मीदवार दो थे। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद फ़ायदा पहुंचाया गया।'' राहुल गांधी ने कहा, ''जब कांग्रेस ने मिलने की मांग की, तो निर्वाचन आयोग ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की। जब आख़िरकार हमारे नेताओं की मुलाकात हुई तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी आपको ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज़्यादा आसान है।''

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ऐसी 'चोरी' है, जिसमें केंद्र से लेकर राज्य तक सभी संस्थाएं शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, ''जब चोरी हुई है और इस चोरी में सभी लोग शामिल हैं। न केवल राज्य, बल्कि केंद्र भी... निर्वाचन आयोग भी... और मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उच्चतम न्यायालय भी।'' उन्होंने सवाल उठाया कि जब उच्चतम न्यायालय को यह मालूम था कि बीजेपी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, तो उसने याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख क्यों निर्धारित की। सिंह ने कहा, ''यह सब मिली-जुली चोरी है।''

क्यों पहाड़ों पर ही रह जाते हैं पर्वतारोहियों के शव?

माउंट एवरेस्ट, जो कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सदियों से इंसानी साहस और महत्वाकांक्षा का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस बर्फीले शिखर को छूने का सपना दुनिया भर के अनगिनत साहसी पर्वतारोही देखते हैं। लेकिन इस खूबसूरत चोटी के पीछे एक अत्यंत डरावना और कड़वा सच भी छिपा हुआ है। इस पर्वत पर विजय पाने की कोशिश में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और उनमें से 200 से अधिक पर्वतारोहियों के मृत शरीर आज भी उसी बर्फीली ऊंचाई पर पड़े हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक विज्ञान और उन्नत तकनीक के इस युग में भी उन शवों को नीचे लाकर उनके परिवारों को सौंपना संभव नहीं हो पाया है। इसके पीछे प्रकृति की अत्यंत क्रूर परिस्थितियां, इंसानी शरीर की जैविक सीमाएं और विज्ञान के कुछ अकाट्य नियम काम कर रहे हैं जो इंसानी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं।

एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान सबसे भयानक चुनौती उस समय शुरू होती है जब कोई पर्वतारोही 8000 मीटर की ऊंचाई की अदृश्य सीमा को पार करता है। पर्वतारोहण की दुनिया में इस ऊंचाई से ऊपर के पूरे क्षेत्र को मृत्यु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इस ऊंचे क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव इतना कम हो जाता है कि हवा में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की मात्रा समुद्र तल के मुकाबले केवल 33 प्रतिशत रह जाती है। इतनी कम ऑक्सीजन में मानव शरीर की कोशिकाएं धीरे-धीरे मरने लगती हैं और मस्तिष्क तथा फेफड़ों में पानी भरने का जानलेवा खतरा बढ़ जाता है। इस स्थान पर खड़े रहकर सांस लेना भी अपने आप में एक महायुद्ध लड़ने जैसा होता है और कृत्रिम ऑक्सीजन के बिना यहाँ कुछ घंटे भी जीवित रहना असंभव है। ऐसी स्थिति में पर्वतारोहियों का पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल अपने आप को जीवित रखने पर केंद्रित होती है। जब इस ऊंचाई पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथी या मार्गदर्शक चाहकर भी उसके शरीर को हिलाने या साथ ले जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरों की मदद करने का प्रयास करना सीधे तौर पर अपनी मौत को आमंत्रण देने जैसा होता है।

इस बर्फीले साम्राज्य में मौत के बाद मानव शरीर की जो भौतिक स्थिति बनती है, वह शवों को नीचे न ला पाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एवरेस्ट के ऊपरी हिस्सों में तापमान अक्सर शून्य से 30 डिग्री से लेकर शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। इस अत्यधिक ठंड के कारण मृत्यु के तुरंत बाद मानव शरीर के भीतर का सारा तरल पदार्थ जम जाता है और शरीर पूरी तरह से पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसके अलावा पर्वतारोहियों के विशेष भारी कपड़े, जूते और अन्य उपकरण भी आसपास की बर्फ और नमी को सोखकर शरीर के साथ ही पूरी तरह से जम जाते हैं। इस प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया के कारण एक सामान्य मानव शरीर का वजन जीवित अवस्था के मुकाबले बढ़कर 100 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक हो जाता है। इतनी तीव्र ढलान वाली, फिसलन भरी और खतरनाक बर्फीली चट्टानों पर 150 किलोग्राम के एक भारी पत्थर जैसे सख्त शव को खींचना या उठाना पूरी तरह से

नामुमकिन कार्य बन जाता है। बर्फ के साथ जुड़ जाने के कारण ये शव पर्वतीय सतह का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें वहां से अलग करने के लिए कुल्हाड़ियों से बर्फ को काटना पड़ता है।

एक मृत शरीर को इतनी ऊंचाई और विकट परिस्थितियों से नीचे सुरक्षित लाने के लिए कम से कम 6 से लेकर 10 अत्यंत कुशल, शारीरिक रूप से सुदृढ़ और स्थानीय पहाड़ी गाइडों की आवश्यकता होती है, जिन्हें शेरपा कहा जाता है। जब ये शेरपा मृत्यु क्षेत्र में इतने भारी वजन को उठाने या खींचने का प्रयास करते हैं, तो उनके अपने शरीर की ऊर्जा और कृत्रिम ऑक्सीजन बहुत तेजी से समाप्त होने लगती है। भारी वजन के साथ खड़ी बर्फ पर संतुलन बनाना बेहद कठिन होता है और पैर फिसलने की एक छोटी सी चूक पूरे बचाव दल को हजारों फीट गहरी खाई में गिरा सकती है। पर्वतारोहण के इतिहास में ऐसे कई दुखद उदाहरण दर्ज हैं जहाँ दूसरों के शवों को बचाने या नीचे लाने के प्रयास में रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने खुद अपनी अमूल्य जान गंवा दी। इसी वजह से पर्वतारोहण समुदायों में यह कठोर नियम सर्वमान्य माना जाता है कि जीवित लोगों की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रहेगी और किसी मृत शरीर को वापस लाने के लिए जीवित इंसानों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।

भौगोलिक और शारीरिक चुनौतियों के अलावा, एवरेस्ट से किसी शव को नीचे लाने का अभियान आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होता है। इस तरह के विशेष और अत्यधिक खतरनाक बचाव कार्यों को आयोजित करने का खर्च 30000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 100000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 25 लाख से लेकर 85 लाख रुपये या उससे भी अधिक बैठता है। इतनी भारी धनराशि खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई न्यूनतम गारंटी नहीं होती कि शव को सुरक्षित नीचे लाया जा सकेगा। कई बार मौसम अचानक खराब हो जाता है, जिससे पूरा मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही, एवरेस्ट पर चढ़ने और उतरने के लिए पूरे वर्ष में केवल कुछ ही दिनों का समय मिलता है जिसे मौसम की अनुकूल खिड़की कहा जाता है। यह समय आमतौर पर मई के महीने में केवल कुछ दिनों के लिए आता है। इस बेहद संक्षिप्त समय सीमा में सैकड़ों पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने की कतार में होते हैं, और ऐसे में किसी शव को खोजने और लाने के लिए मार्ग को अवरुद्ध करना या समय नष्ट करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता है।

इस बेहद दुखद स्थिति का एक और दार्शनिक और कड़वा पहलू यह है कि समय के साथ ये शव एवरेस्ट के रास्तों के स्थायी निशान या संकेतक बन गए हैं। पर्वत पर चढ़ने वाले नए पर्वतारोही इन शवों को देखकर अपने मार्ग, ऊंचाई और दूरी का अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध शव जिसे हरे जूते वाले पर्वतारोही के नाम से जाना जाता है, वह एक भारतीय पर्वतारोही का माना जाता है, जो 1996 के एक भयानक बर्फीले तूफान में मारे गए थे। इसी तरह एक और शव है, जिसे लोग सोती हुई सुंदरी के नाम से याद करते हैं। ये शव वहाँ आने वाले हर इंसान को प्रकृति की सर्वोच्चता और मानव जीवन की क्षणभंगुरता की लगातार याद दिलाते रहते हैं। कई परिवारों ने भी अंततः इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और वे चाहते हैं कि उनके प्रियजनों का शव उसी पर्वत की गोद में हमेशा के लिए विश्राम करे। एवरेस्ट का यह डरावना सच हमें यह सिखाता है कि मानव विज्ञान और तकनीक चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल प्रकृति के क्रूर नियम चलते हैं और वहां इंसान की जिद की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मौत के बाद भी नीचे न लाए जा सकने वाले ये शव एवरेस्ट के गौरव के साथ जुड़े उस अनंत सन्नाटे को बयां करते हैं जो इंसानी अहंकार को अपनी सीमाओं में रहने की चेतावनी देता रहता है।

महेन्द्र तिवारी

पश्चिम एशिया में युद्ध के प्रभाव से निबटना भारतीयों की चुनौती

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

युद्ध कोई भी हो उसका नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में फैली अंशाति का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध की जिसमें दुनियां के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। व्यापार टूट रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पश्चिम एशिया दशकों से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन 2023 के बाद से इज़राइल-हमास, इज़राइल-हिज़बुल्लाह और इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ा टकराव इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले आया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक दूरी की खबर नहीं है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी और खाड़ी देशों से व्यापार का सीधा जुड़ाव रखता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है - सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान और कुवैत मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। जब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं। 2024-2025 में इज़राइल-ईरान मिसाइल हमलों के दौरान ब्रेंट क्रूड 90 पार कर गया था। भारत के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल-डीजल, बढ़ती महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइनों का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ता है। इस अशांति से 90 लाख भारतीयों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है।

यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये हर साल 35-40 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। युद्ध बढ़ने पर दो तरह का खतरा है। पहला, अगर खाड़ी देश युद्ध में खिंचे तो वहां नौकरियां घटेंगी और भारतीयों की वापसी शुरू होगी। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1.5 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करना पड़ा था। दूसरा, अगर ईरान-इज़राइल संघर्ष बढ़ा तो ईरान में 4000 और इज़राइल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनेगी। भारत ने ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन अजेय के जरिए पहले भी नागरिकों को निकाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर निकासी लॉजिस्टिक रूप से जटिल है। युद्ध के कारण व्यापार और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक साझेदार हैं। I22 और आईएमईसी कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने के लिए बनी थीं। लेकिन युद्ध के माहौल में निवेश रुक जाता है। लाल सागर में हूती हमलों के बाद शिपिंग बीमा महंगा हुआ और भारत-यूरोप व्यापार पर असर पड़ा। अगर सूएज नहर या होर्मुज बंद हुआ तो भारत का 80% विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।

भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा 'संतुलन' पर टिकी रही है। भारत इज़राइल से रक्षा और तकनीक लेता है, अरब देशों से तेल और निवेश, और ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चाहता है। वर्तमान युद्ध ने इस संतुलन को कठिन बना दिया है। एक तरफ चुनना पड़ा तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने यूएन में शांति की अपील की है, लेकिन सीधे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। ये तटस्थता कूटनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन घरेलू राजनीति में इसकी आलोचना भी होती है। इस युद्ध का असर घरेलू राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करता है। फिलिस्तीन और इज़राइल पर भारत के रुख को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण दिखता है। इसके अलावा, अगर तेल 120 डॉलर पार गया तो भारत सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? रणनीतिक तेल भंडार : भारत ने पहले ही 5.33 मिलियन टन का भंडार बना रखा है, जो 9-10 दिन चल सकता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक स्रोत : रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करना। निकासी योजनाः खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखना और नौसेना की तत्परता बढ़ाना।

कूटनीतिक सक्रियताः भारत जी20 और बीआरआईसी के मंच पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठा सकता है।

पश्चिम एशिया में युद्ध भारत के लिए दूर का युद्ध नहीं है। ये हमारे रसोई गैस के दाम, खाड़ी में काम करने वाले भाई-बहन की नौकरी और रुपये की कीमत से जुड़ा है। भारत की ताकत ये है कि वो अब भी अरब देशों, इज़राइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इस संतुलन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है अगले 6-12 महीने महंगाई और अनिश्चितता के साथ जीना।

परमाणु शक्ति संपन्न भारत में कब होगी बालिका शिक्षा शत-प्रतिशत

'यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।' महात्मा ज्योतिराव फुले।

भारत विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपराओं वाला देश रहा है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व को शिक्षा का प्रकाश दिया। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना था। गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने सिद्ध किया था कि भारतीय संस्कृति में नारी शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। किंतु मध्यकालीन सामाजिक रूढ़ियों और औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से बालिका शिक्षा पिछड़ती चली गई। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में ऐसे कर्मचारियों का वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक कार्यों को संचालित कर सके। आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रसार में इस शिक्षा प्रणाली का योगदान रहा, किंतु इसने भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षण को काफी हद तक हाशिए पर पहुंचा दिया। उस समय महिलाओं की शिक्षा लगभग नगण्य थी। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधा थीं।

समाज सुधारकों का योगदान

ऐसे कठिन समय में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने बालिका शिक्षा की अलख जगाई। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला आधुनिक विद्यालय प्रारंभ किया।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों को नई दिशा दी। बाद में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना।

डॉ. अंबेडकर का प्रसिद्ध संदेश 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।' स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर लगभग 18 प्रतिशत थी। महिलाओं की साक्षरता तो 10 प्रतिशत से भी कम थी। संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार माना। समय-समय पर कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा नई शिक्षा नीति 2020 जैसे प्रयास किए गए। इन प्रयासों से शिक्षा का दायरा बढ़ा और लड़कियों की विद्यालयों तक पहुंच बेहतर हुई।.आज भारत की साक्षरता दर 77 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि महिला साक्षरता दर 70 प्रतिशत से अधिक है। यह प्रगति उत्साहजनक है, किंतु अभी भी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर बना हुआ है।

विश्व के सर्वाधिक शिक्षित देशों से सीख

विश्व में फिनलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और नॉर्वे जैसे देशों की शिक्षा व्यवस्था विश्व में आदर्श मानी जाती है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन कौशल विकसित करना है। वहां बच्चों पर अनावश्यक परीक्षा का दबाव नहीं होता। शिक्षकों को अत्यंत सम्मान और स्वायत्तता प्राप्त है। बालिका और बालक के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। सिंगापुर ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन बनाया। वहां विज्ञान, गणित, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा को उद्योगों और रोजगार से जोड़ा गया है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अनुशासन, नैतिकता, समयबद्धता और तकनीकी दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप ये देश सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद आर्थिक महाशक्ति बन गए।

भारत में प्रतिभा की कोई कमी कभी भी नहीं रही है, किंतु शिक्षा व्यवस्था अभी भी परीक्षा-केंद्रित बनी हुई है। रटंत प्रणाली, विद्यालयों की असमान गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव आज भी चुनौतियां हैं।नई शिक्षा नीति 2020 ने इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें मातृभाषा आधारित शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षण और बहुविषयक अध्ययन पर बल दिया गया है। किंतु इसके वास्तविक लाभ तभी मिलेंगे जब इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। बालिका शिक्षा का सत प्रतिशत होना इसलिए भी आवश्यक है कि शिक्षित बेटी, समृद्ध परिवार

एक शिक्षित महिला अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार प्रदान करती है। वह अगली पीढ़ी की प्रथम शिक्षिका होती है।सामाजिक कुरीतियों का अंत भी।बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को समाप्त करने में शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है। विश्व बैंक सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि महिलाओं की शिक्षा में निवेश किसी भी देश के आर्थिक विकास को तीव्र गति देता है। यदि भारत की प्रत्येक बेटी शिक्षित होगी तो देश की उत्पादकता और आर्थिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। आज महिलाएं विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रशासन, राजनीति, सेना और उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। शिक्षा उन्हें नेतृत्व और नवाचार की शक्ति प्रदान करती है। महापुरुषों की दृष्टि में नारी शिक्षा

स्वामी विवेकानंद ने कहा 'राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड वहां की महिलाओं की स्थिति है। 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का मत था कि 'महिलाओं का सशक्तिकरण और शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। 'पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 'एक महिला को शिक्षित करना एक पीढ़ी को शिक्षित करना है। ' इक्कीसवीं सदी ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की सदी है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश की प्रत्येक बेटी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी। शिक्षा केवल विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक चेतना, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय विकास का आधार है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली से लेकर नई शिक्षा नीति तक भारत ने लंबी यात्रा तय की है, किंतु अभी मंजिल दूर है। यदि सरकार, समाज, परिवार और शैक्षणिक संस्थान मिलकर बालिका शिक्षा को शत-प्रतिशत अनिवार्य बनाने का संकल्प लें, तो भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति बनेगा, बल्कि सबसे विकसित और ज्ञानवान राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में भी खड़ा होगा। क्योंकि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों में नहीं, बल्कि उसकी शिक्षित बेटियों की आंखों में स्वप्न बनकर पलता है। **संजीव ठाकुर**

कविता

शिक्षा का कवच।

शिक्षा का कवच।
कुछ देना ही तो आइये,
नन्हीं बालिकाओं को
स्वर्ण के गहने नहीं,
शिक्षा का कवच दें।
उनकी हथेलियों में
रोटी के साथ-साथ
कुछ अक्षर भी रख दें,
जो भूख से जुझतीं
उन्हें ज्ञान की कुंजी दें
अँधेरे बंद कमरों में
रोशन-दान बनती,
ज्ञान की रोशनी के लिए
बंद रास्तों पर
एक नया आकाश फैला देती,
उनकी आँखों में
सिर्फ़ स्वप्न ना रखें ,
उन तक पहुँचने के पंख भी दें।
उन्हें ज्ञान दें कि
अपने हिस्से की धूप
खुद चुन सकें।
किताबें जब उनके हांथों में होंगी,
तो सदियों के कई बोझ
आप उतर जाएँगे।
कलम उँगलियों से चलेंगीं
तक़दीर की कविता भी
लिखी जाएगी।
शिक्षित बालिका
अपना जीवन ही नहीं संवारती,
आने वाली पीढ़ियों के लिए
उजला दीप बन जाती।
आइये,
बेटी को शिक्षा का रक्षा-कवच दें,
ताकि वह
अपने सपनों, अपने अधिकारों
अपने अस्तित्व की रक्षा
स्वयं कर सके।

संजीव ठाकुर

दैनिक राशिफल

मेष आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 9

वृषभ पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।
शुभ रंगः सफेद 7 शुभ अंकः 6

मिथुन व्यापार में लाभ के संकेत हैं। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 5

कर्क पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं।
शुभ रंगः क्रीम 7 शुभ अंकः 2

सिंह आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंगः सुनहरा 7 शुभ अंकः 1

कन्या कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 7

तुला दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंगः गुलाबी 7 शुभ अंकः 6

वृश्चिक गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।
शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 8

धनु भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 3

मकर कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं। शुभ रंगः नीला 7 शुभ अंकः 8

कुंभ नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।
शुभ रंगः आसमानी 7 शुभ अंकः 4

मीन मानसिक शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।
शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 7

उपाय सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और अपने इष्टदेव का स्मरण करें। इससे दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

स्त्री नहीं, सोच घर बनाती और बिगाड़ती है

यह कौन-सा नियम है जहां दोष पहले से तय होता है?

परिवार की सफलता और विफलता का बोझ केवल महिलाओं पर क्यों?

हमारे समाज में कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर कभी बहस नहीं हुई, फिर भी वे अंतिम सत्य मान लिए गए हैं। उन्हीं में से एक है– 'घर बनाती भी स्त्री है और और घर बिगाड़ती भी वही है।' परिवार में सुख, संस्कार और रिश्तों में मधुरता हो तो कहा जाता है– 'बहू बहुत अच्छी मिली है।' लेकिन तनाव या विघटन होते ही आरोप सबसे पहले उसी पर आता है, मानो घर किसी एक व्यक्ति द्वारा चलने वाली व्यवस्था हो। यह केवल सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जिसने स्त्री के त्याग को कर्तव्य और उसकी पीड़ा को नियति मान लिया है। प्रश्न यह नहीं कि स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है या नहीं–वह निस्संदेह है, बल्कि यह है कि क्या वह अकेली जिम्मेदार है? यदि घर बनाना सामूहिक प्रक्रिया है, तो उसका बिगड़ना भी सामूहिक विफलता है। फिर हर बार कठघरे में केवल स्त्री ही क्यों? यह प्रश्न परिवार के भविष्य से जुड़ा है।

घर एक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं

हम अक्सर घर को चार दीवारों और छत का नाम मान लेते हैं, जबकि वह भावनाओं, संघर्षों और रिश्तों से बनी एक जीवंत व्यवस्था है। वहां भावनाएं, उम्मीदें, समझौते और रिश्ते सभी रहते हैं। इसमें माता, पिता, बच्चे और बुजुर्ग सभी की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। फिर भी यह धारणा बना ली गई है कि घर की सफलता का श्रेय पूरे परिवार को मिलेगा, लेकिन उसकी विफलता का दोष केवल स्त्री पर जाएगा। क्या कोई खेत केवल बारिश से लहलहाता है, क्या कोई वृक्ष केवल जड़ों से खड़ा रहता है, क्या कोई नदी केवल एक स्रोत से बहती है? जब हर प्राकृतिक संरचना सामूहिक योगदान से बनती है, तो परिवार जैसी जटिल संस्था की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर कैसे डाली जा सकती है?

लक्ष्मी बनाकर बोझ क्यों?

भारतीय समाज ने स्त्री को सम्मान देने के लिए उसे देवी, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कहा, लेकिन यह सम्मान कई बार बोझ बन गया। देवी बना देने से उसके इंसान होने का अधिकार सीमित हो गया–उसके थकने, रोने, गलती करने और अपनी इच्छाएँ रखने की गुंजाइश कम हो गई। उससे अपेक्षा की गई कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराए, सबको जोड़े रखे और स्वयं को सबसे अंत में रखे। विडंबना यह है कि जिस सम्मान के कारण उसे ऊँचा स्थान दिया गया, उसी पर इतना दायित्व डाल दिया गया कि वह दबने लगी, और जब वह थक गई तो कहा गया– 'घर संभाल नहीं पाई। '

नई भूमिकाएँ, पुराने बोझ

आज की स्त्री केवल रसोई तक सीमित नहीं है; वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी और उद्यमी बनकर परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बन रही है। फिर भी जिम्मेदारियाँ उसके साथ समान रूप से साझा नहीं की गई हैं–दफ्तर से लौटने के बाद भी रसोई, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारियों का निर्वाह और बुजुर्गों की देखभाल अधिकतर उसी पर बनी रहती है। समाज ने उसके कंधों पर नए दायित्व जोड़ दिए, लेकिन पुराने बोझ कम नहीं किए। यह व्यवस्था उसे सशक्त नहीं बनाती, बल्कि धीरे-धीरे भीतर से थका देती है। और जब यह थकान या असंतोष सामने आता है, तो उसे 'स्त्री का स्वभाव' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

समस्या स्त्री नहीं, सोच है

दरअसल समस्या स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि सोच है–जो घर की जिम्मेदारी स्त्री पर और अधिकार पुरुष पर मान लेती है, और त्याग को केवल स्त्री का गुण समझती है। यही सोच पुरुष की अनुपस्थिति को मजबूरी और स्त्री की थकान को कमजोरी मानती है। घर मतभेद या आर्थिक संकट से नहीं टूटते, बल्कि तब टूटते हैं जब संवाद और सम्मान समाप्त हो जाता है और लोग परिस्थितियों से लड़ने के बजाय एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसलिए किसी घर को बचाना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी।

साझेदारी से सशक्त परिवार

सशक्त परिवार की पहचान विवादों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनका मिलकर समाधान है। जहां पति समझे कि परिवार केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं चलता, पत्नी महसूस करे कि उसके संघर्षों को समझा जा रहा है, बच्चे जिम्मेदारियां सीखें और बुजुर्ग अनुभव साझा करें, दबाव नहीं। परिवार तब मजबूत होता है जब हर सदस्य स्वयं को सहभागी माने, बोझ नहीं। सम्मान बड़े उपहारों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार–एक धन्यवाद, एक क्षमा, संवेदनशील संवाद और एक-दूसरे की थकान को समझने से आता है। यही छोटे प्रयास बड़े संकटों को भी कम कर देते हैं।

उंगली नहीं, आईना उठाओ

जब भी कोई घर टूटे, समाज को अपनी पुरानी आदत बदलनी होगी। हर बार स्त्री को दोषी ठहराने से न घर बचते हैं, न रिश्ते। घर टूटने के कारण गहरे हैं–अहंकार, संवादहीनता, असमान जिम्मेदारियां और सम्मान की कमी। स्त्री घर की धुरी हो सकती है, पर वह अकेला पहिया नहीं है; परिवार एक रथ है जिसे सभी मिलकर चलाते हैं। एक पहिया टूट जाए तो रथ नहीं चलता। लेकिन यदि बाकी पहिए भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं तो फिर दोष केवल एक पहिए का नहीं होता। समय है कि स्त्री को देवी नहीं, इंसान मानकर साझेदारी दी जाए। घर एक के त्याग से नहीं, सबके सहयोग से बनता है, और उसके बिगड़ने का दोष भी किसी एक पर नहीं डाला जा सकता। समाज जब यह सरल सत्य स्वीकार करेगा, तभी परिवार अधिक न्यायपूर्ण, मानवीय और मजबूत बनेंगे। तब घरों में कटघरे नहीं, संवाद होंगे; आरोप नहीं, सहभागिता होगी। तब समझ आएगा कि घर बनाने वाली केवल स्त्री नहीं, बल्कि वह सोच है जो 'मैं' से ऊपर उठकर 'हम' में विश्वास करती है।

कृति आरके जैन

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

सैंकड़ों वर्ष पुरानी बड़ा हनुमान मंदिर की प्रतिमा गिरी, नई प्रतिमा होगी स्थापित

बिसवां (सीतापुर)। नगर के महमूदाबाद रोड स्थित प्राचीन बड़ा हनुमान मंदिर में स्थापित सैकड़ों वर्ष पुरानी हनुमान प्रतिमा शुक्रवार को अचानक गिर गई। घटना की जानकारी सुबह होते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा ने बताया कि यह प्रतिमा गोबर, मिट्टी, चूना और शहद जैसी पारंपरिक सामग्रियों से दीवार पर निर्मित की गई थी तथा इसे सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। उन्होंने बताया कि समय के प्रभाव से प्रतिमा गिर गई है और अब मंदिर में विधि-विधान के साथ नई हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने मंदिर को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। घटना के बाद नगर में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

उत्तर प्रदेश खनन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 अधिकारियों का तबादला

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भूतत्व एवं खनिकर्म के एक सहायक भूवैज्ञानिक, एक रसायन अधिकारी, एक क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी और 11 जिला खान अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खनन बहुल सहारनपुर, चित्रकूट, फतेहपुर के खनिज अधिकारी भी बदल दिये गये हैं। जिला खान निरीक्षक नरेश कुमार को संत कबीर नगर से फतेहपुर भेजा गया है। शिव दयाल सिंह को मैनपुरी से सुलतानपुर भेजा गया है। विपेद्र कुमार राजभर को फतेहपुर से श्रावस्ती, मन्टू कुमार सिंह को चित्रकूट से मैनपुरी, सुभाष सिंह को पीलीभीत से मथुरा, विवेक कुमार को श्रावस्ती से चित्रकूट, अक्षय कुमार को मथुरा से संतकबीरनगर, प्रांजुल सिंह को उन्नाव से पीलीभीत, गोपाल कृष्ण दत्ता को मुख्यालय लखनऊ से ललितपुर, अनंत कुमार को कानपुर देहात से सहारनपुर और सुभाष सिंह को सहारनपुर से कानपुर देहात भेजा गया है। इसी तरह सहायक भू वैज्ञानिक सोमेन्द्र तिवारी को मुख्यालय लखनऊ से फतेहपुर का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। सहायक रसायन अधिकारी डॉ. सुशील कुमार को बिजनौर का खान अधिकारी बनाया गया है। क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी अनन्त कुमार सिंह को क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी अयोध्या के साथ बाराबंकी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

लखनऊ और नोएडा के बीच 15 जून से शुरू होगी पहली कमर्शियल फ्लाइट, सफर करेंगे 75 बिजनेसमैन; सारी टिकट बुक

लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ औद्योगिक नगरी नोएडा से 15 जून को सीधी विमान सेवा से जुड़ जाएगी। लखनऊ से नोएडा के लिए 15 जून से विमान सेवा शुरू हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए संचालित होने वाली पहली कमर्शियल विमान सेवा में नोएडा के 75 प्रमुख कारोबारी 15 जून को लखनऊ से उड़ान भरेंगे। यह परिवार रविवार को लखनऊ पहुंचेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर भारत के सबसे बड़े आर्थिक इंजन के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन 75 कारोबारी परिवारों में रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं। इनका योगदान नोएडा और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी), उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की रुचि इस क्षेत्र में और बढ़ेगी। इससे निवेश, रोजगार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी।

सारी टिकट बुक इंडिगो एयरलाइन के विमान 6ई-2278 प्रतिदिन सुबह 7:05 बजे लखनऊ से रवाना होकर 8:05 बजे नोएडा पहुंचेगी। नोएडा एयरपोर्ट का कोड डीएक्सएन होगा। इस विमान की 15 जून की सभी सीटें फुल हो गई हैं।

भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने किया स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं की सराहना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त निरीक्षण टीम ने शुक्रवार को क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मड़िया सेमरी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवथाना का विस्तृत निरीक्षण कर वहां संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण दल में डॉ. अनुराधा जैन, पंकज शाह (कंसल्टेंट), राम नरेश आजाद (डीजीएम कम्युनिटी प्रोसेस), अनूप श्रीवास्तव (रीजनल मैनेजर), ज्ञान प्रकाश सहित जिले से डीसीपीएम रिजवान, टीएसयू की श्वेता एवं बीसीपीएम विमल त्रिपाठी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, अभिलेखों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन का बारीकी से अवलोकन किया। टीम ने चिकित्सकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, लैब टेक्नीशियनों, फार्मासिस्टों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर सेवाओं के संचालन और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रम, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, लैब सेवाओं, औषधि वितरण व्यवस्था तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। टीम ने लाभार्थियों से भी बातचीत कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की तथा विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

संयुक्त टीम ने स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए अधीक्षक डॉ. अमित कपूर एवं समस्त स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इससे पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, इमरजेंसी, प्रयोगशाला, एक्स-रे इकाई, जेएसवाई वार्ड एवं प्रसव कक्ष का भ्रमण कर मरीजों तथा उनके तीमारदारों से बातचीत की। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध लैब, एक्स-रे, आपातकालीन चिकित्सा एवं प्रसव सेवाओं की प्रशंसा करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त टीम तथा मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम पर होगा इस बार का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होगी कोशिश

लखनऊ। बढ़ती उम्र में स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए योग को प्रभावी माध्यम बताते हुए इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' (स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग) निर्धारित है। 21 जून को योग दिवस है। जिससे पहले 14 जून को राज्य में ऑनलाइन योग कराया जाएगा। इसमें भागीदारी के लिये टोल फ्री नम्बर-1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल से पंजीकरण कराया जा सकता है। सरकार इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराने का प्रयास करेगी। फिर 15 से 21 जून तक चलेगी योग सप्ताह। इसमें जिला मुख्यालयों, तहसीलों, ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन सुबह सामूहिक योगाभ्यास होंगे। आयोजन में पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) सामग्री काएआ उपयोग होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुये शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि योग को जन-आंदोलन बनाने के लिये प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। इस बार चिकित्सालयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, पुलिस स्टेशनों, बस स्टेशनों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर योग दिवस का प्रचार किया जायेगा।

लखनऊः दुष्कर्म और धोखाधड़ी का आरोपित इलाज के दौरान चलरूसे फरार, दो सिपाहियों पर मुकदमा

● दुष्कर्म और धोखाधड़ी का आरोपी बंदी केजीएमयू से फरार।

● इलाज के दौरान अस्पताल से भागा हैदर अली।

● दो सुरक्षाकर्मियों पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज। तक कागजों में विकास, बिना कार्य निकाले जा रहे लाखों रुपये

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सरोजनी नगर थाने से बीते वर्ष सात जनवरी को धोखाधड़ी, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में जेल भेजा गया बंदी इलाज के दौरान शुक्रवार को किंग जार्ज मेडिकल कालेज (केजीएमयू) से फरार हो गया। जिला जेल के जेलर ने ओडिशा के बालासोर निवासी बंदी व सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों के खिलाफ चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने तहरीर में बताया कि सरोजनी नगर पुलिस ने ओडिशा के बालासोर स्थित चांदीपुर गांव निवासी बंदी हैदर अली को सात जनवरी 2025 को धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपित को जेल भेजा था। वह जिला कारागार में निरुद्ध था।

जेल के चिकित्सालय में भर्ती कराया

31 मई 2026 को उसे खून की उल्टी और अन्य समस्याएं होने पर जेल के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर चार जून को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया। बलरामपुर अस्पताल से उसे केजीएमयू रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे चेकिंग के दौरान बंदी रक्षक नागेश चंद्र सरोज ने बताया कि हैदर का कुछ पता नहीं चल रहा है। काफी तलाशने पर भी वह नहीं मिला। उसकी निगरानी हेतु तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ चौक कोतवाली में लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर बंदी की तलाश में टीम गठित की गई है।

'हाईस्कूल पास न होने पर सही मानी जाएगी सर्विस बुक में दर्ज डेट ऑफ बर्थ'; इलाहाबाद ।।ष्ट का अहम फैसला

● सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।

हाईस्कूल पास न होने पर यह नियम लागू।

कर्मचारी की जानकारी के बिना बदलाव अवैध।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में दर्ज जन्मतिथि सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम-2 का हवाला देते हुए कहा कि सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि को ही सही माना जाएगा। बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट, अलीगढ़ में कार्यरत एक श्रमिक से जुड़ा था। उनकी नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी। मेडिकल परीक्षण के आधार पर उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1967 दर्ज की गई। इसके अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2027 को होनी थी।

हालांकि बाद में एक जांच और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल 1966 दर्ज कर दी गई। इसके आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख बदलकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई। अदालत ने पाया कि वर्ष 1966 की जन्मतिथि बाद में व्हाइट इंक का उपयोग कर दर्ज की गई थी। इसके लिए जिस ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भरोसा किया गया। वह नियमों के तहत मान्य दस्तावेज नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी को बिना सुने और उसकी जानकारी के पीछे इस तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख बदलने संबंधी आदेशों को रद करते हुए कहा कि सेवा पुस्तिका में मूलरूप से दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।

यूपी में बिजली व्यवस्था में प्रशासनिक मतभेद पर अजय राय ने जताई चिंता

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बिजली विभाग में प्रशासनिक मतभेद और नियामक संस्थाओं को निष्प्रभावी किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिजली व्यवस्था में सुधार, ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी लिखा है कि ऊर्जा मंत्री स्वयं पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उन्हें बताए बिना फैसले ले रहे हैं।

प्रशासनिक मतभेद नहीं बल्कि सरकार की गंभीर विफलताः अजय राय

ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच टकराव का खामियाजा प्रदेश की जनता झेल रही है। उन्होंने कहा है कि यह सामान्य प्रशासनिक मतभेद नहीं बल्कि सरकार की गंभीर विफलता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि ऊर्जा मंत्री के आरोप सही हैं, तो मुख्यमंत्री द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि आरोप गलत हैं को ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूकता अभियान आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय जिला जज/अध्यक्ष आशीष जैन जी के आदेशानुसार एवं माननीय श्री आलोक यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सीतापुर के मार्गदर्शनमें बाल श्रम उन्मूलन एवं शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विधिक जन-जागरूकता कार्यक्रम रामनगर सचिवालय मे आयोजित किया गया । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को बाल श्रम जैसी कुप्रथा के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना रहा।पी एल वी रहमत अंसारी ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, बाल अधिकारों एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय या कार्य में मजदूरी कराना कानूनी रूप से पूर्णतः प्रतिबंधित है। बच्चे स्कूल के बाद या छुट्टियों में अपने परिवार के ऐसे व्यवसाय में मदद कर सकते हैं जो खतरनाक न हो।14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है।बाल श्रम अब एक संज्ञेय अपराध है। नियम तोड़ने वाले नियोक्ताओं (काम पर रखने वालों) को 6 महीने से 2 साल तक की जेल या ?20,000 से ?50,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।यदि कोई व्यक्ति या नियोक्ता दूसरी बार इस अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे 1 साल से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही आमजन से अपील किया कि यदि कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे तो इसकी सूचना विभागों एवं हेल्पलाइन नंबरों जैसे - 1098, 112,15100 पर अवश्य दें। कार्यक्रम में अधिकार मित्र श्रीमती उर्मिला ने उपस्थित नागरिकों से बाल श्रम के विरुद्ध अभियान में सहयोग देने तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये शपथ दिलायी।बाल श्रम बच्चों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास के अधिकारों का हनन है। बच्चों को श्रम में लगाने के बजाय विद्यालय भेजना प्रत्येक अभिभावक एवं नागरिक की नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षित बच्चे ही देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति सदस्य संजय शुक्ला, लेबर ऑफिसर श्री एल डी पाल, ग्राम प्रधान सहित विभिन्न गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय के लोगों ने सहभागिता कर बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी पर मिलेगा 6.50% ब्याज, 3.73 करोड़ ग्राहकों का 300 करोड़ बन रहा इंटरेस्ट

लखनऊ। बिजली कंपनियों द्वारा जून में बिजली बिल के साथ वसूले जा रहे 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क के विरोध के बीच उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी धनराशि पर 6.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का निर्णय किया गया है। जिन उपभोक्ताओं के जून में अदा किए बिल में ब्याज की धनराशि समायोजित नहीं हो सकेगी उन्हें जुलाई में इसका फायदा दिया जाएगा। 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग 300 करोड़ रुपये ब्याज का मिलने का अनुमान है। दरअसल, विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47 तथा विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 4.20 के तहत जमा सिक्योरिटी धनराशि पर उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष एक अप्रैल को लागू बैंक दर से ब्याज पाने का वैधानिक अधिकार है।

2025 में 6.50 प्रतिशत थी बैंक ब्याज दर

एक अप्रैल 2025 को बैंक ब्याज दर 6.50 प्रतिशत थी। उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी धनराशि पर बन रहे ब्याज का समायोजन बिजली कंपनियों के बिलिंग साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की औसत जमा सिक्योरिटी लगभग 4,616 करोड़ रुपये थी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का मिलान कर लें। यदि किसी उपभोक्ता को सिक्योरिटी धनराशि पर देय ब्याज का लाभ नहीं मिल रहा है तो संबंधित वितरण कंपनी के अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।

यूपी में गोरखपुर समेत 6 एयरपोर्ट के विस्तार में आई तेजी, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बूस्ट

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति दी है। गोरखपुर, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन, निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए सिविल टर्मिनल के विकास का कार्य तेज किया गया है। इसके लिए भारतीय वायुसेना की 42.14 एकड़ भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों के विस्थापन का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

अलीगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 275.74 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

वर्तमान में यहां से औसतन 12 उड़ानों का संचालन हो रहा है। आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल टर्मिनल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। यहां लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

'Prospect of Power Scenario in Uttar Pradesh: Present and Vision 2047' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ द्वारा दिनांक 12 जून 2026 को इंजीनियर्स भवन, रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में 'Prospect of Power Scenario in Uttar PradeshÑ Present and Vision 2047' विषय पर एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश की वर्तमान विद्युत स्थिति, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा वर्ष 2047 तक के संभावित विद्युत परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की गई। संगोष्ठी के प्रारम्भ में प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1327 यूनिट (kWh) रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह मात्र 723 यूनिट प्रति व्यक्ति थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वर्तमान में प्रदेश की अधिकतम विद्युत मांग लगभग 33,000 मेगावाट है, जबकि वर्ष 2047 तक इसके बढ़कर लगभग 1,56,000 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है। विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार की आवश्यकता होगी। वर्ष 2047 के परिदृश्य पर चर्चा करते हुए बताया गया कि आने वाले वर्षों में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, मेट्रो रेल परियोजनाएँ, स्मार्ट सिटी, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण विद्युत मांग में कई गुना वृद्धि होगी। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का व्यापक उपयोग करना होगा। विशेषज्ञों ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इं. वी. बी. सिंह, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष (IP President) भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्युत किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला है तथा उत्तर प्रदेश ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा दक्षता एवं आधुनिक विद्युत अवसंरचना के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं उद्योग जगत से नवाचार और नई तकनीकों को अपनाकर सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इं. आशुतोष दीक्षित, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, यूपीपीटीसीएल, लखनऊ ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़, विश्वसनीय तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विद्युत मांग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन अवसंरचना का समयबद्ध विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्युत हानियों को कम करने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Energy Storage Systems), डिजिटल विद्युत प्रबंधन, रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा स्मार्ट मीटरिंग जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते समावेशन के साथ विद्युत नेटवर्क को अधिक लचीला एवं बुद्धिमान बनाना होगा ताकि मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तकनीकी नवाचार, कुशल मानव संसाधन तथा दीर्घकालिक योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम के वक्ता डॉ. अवधेश कुमार गुप्ता, निदेशक (भूमि एवं परिसंपत्ति), स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने 'नए पावर प्लांट के लिए प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियां

' विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश में विद्युत मांग में होने वाली तीव्र वृद्धि को देखते हुए नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना अपरिहार्य होगी, किन्तु इसके साथ पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी। उन्होंने तापीय विद्युत संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, फ्लाई ऐश प्रबंधन, जल उपयोग तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. गुप्ता ने कहा कि भविष्य के विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों, उच्च दक्षता वाली प्रणालियों तथा कठोर प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप विकसित करना होगा। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी), कार्बन कैप्चर तकनीक तथा नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता देनी होगी। विशेष वक्ता इं. राकेश गोयल, फ्रीलांस कंसल्टेंट ने 'उत्तर प्रदेश में सत्ता की संभावनाओं का परिदृश्यः वर्तमान और भविष्य की दृष्टि' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तीव्र आर्थिक प्रगति, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण आगामी वर्षों में विद्युत मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि, ईंधन स्रोतों की उपलब्धता तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों जैसे ईंधन आपूर्ति, पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन, बढ़ती ऊर्जा मांग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सौर एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास तथा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 के विजन को साकार करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश तथा सतत विकास आधारित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय वक्ता इं. जी.एम. पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष (प्रोजेक्ट्स), एनकोटेक इंडस्ट्रीज ने 'विज़न के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और औद्योगिक ऊर्जा की ज़रूरतें 2047' विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी एवं शहरी विकास योजनाओं को देखते हुए विद्युत अवसंरचना का व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की विद्युत मांग में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है, जिसके लिए उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं से कहीं अधिक सक्षम बनाना होगा। उन्होंने उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों, आधुनिक उपकेंद्रों, स्मार्ट ग्रिड प्रणाली, ऊर्जा भंडारण सुविधाओं तथा डिजिटल निगरानी तंत्र के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास की आधारशिला होती है तथा निवेश आकर्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए विद्युत नेटवर्क को अधिक लचीला, सक्षम एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाना समय की आवश्यकता है। अंत में उन्होंने वर्ष 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, पर्याप्त निवेश तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता इं. वी. पी. सिंह, अध्यक्ष, आई.ई.आई. उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का आधार एक मजबूत एवं विश्वसनीय विद्युत व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 के विजन को साकार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों एवं अभियंताओं को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम के संयोजक इं. जी.एम. पाण्डेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य वक्ताओं एवं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान का परिचय कराया तथा संगोष्ठी विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में संस्था के मानद सचिव इं. एन. के. निषाद ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

संक्षिप्त खबरें

बेंगलुरु बनेगा चेस का नया पावरहाउस, ग्लोबल चेस लीग के सीज़न 4 की करेगा मेजबानी

ग्लोबल शतरंज लीग (जीसीएल) का चौथा सत्र तीन सितंबर से बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। लीग आयोजकों ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। टेक महिंद्रा और शतरंज की वैश्विक संचालक फिडे की संयुक्त पहल के रूप में शुरू हुई ग्लोबल शतरंज लीग ने शतरंज के पारंपरिक प्रारूप में कई नए बदलाव किए हैं। इसमें फ्रेंचाइजी आधारित टीमें, मिश्रित (पुरुष और महिला) टीम संयोजन तथा तेज गति वाले मुकाबलों का प्रारूप शामिल है। चौथे सत्र में भी दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी टीम आधारित प्रारूप में खिताब के लिए मुकाबला करते नजर आएंगे। ग्लोबल शतरंज लीग के आयुक्त गौरव रक्षित ने कहा, ग्लोबल शतरंज लीग की स्थापना शतरंज को वास्तव में एक वैश्विक दर्शक खेल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। चौथे सत्र का बेंगलुरु में आयोजन लीग के साथ-साथ खेल के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहीं से शतरंज के नए अध्याय की शुरुआत होगी। फिडे अध्यक्ष आर्कादी द्वोरकोविच ने कहा, हमें ग्लोबल शतरंज लीग के चौथे सत्र को बेंगलुरु में आयोजित करते हुए खुशी हो रही है। भारत वैश्विक शतरंज आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और बेंगलुरु इस गति को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श मंच प्रदान करता है। पिछले सत्रों में भारत के शीर्ष ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा, डी. गुकेश और महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद भी इस लीग का हिस्सा रह चुके हैं।

बेहतर होगी 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी', द्वारका, उत्तम नगर और ग्रामीण इलाकों के लिए 3 नए बस रूट शुरू

पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम ने शहर में 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (मेट्रो या मुख्य अड्डे से घर तक की दूरी) को बेहतर बनाने के लिए तीन नए बस रूट शुरू किए हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन रूटों का विस्तार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि वे आसानी से मेट्रो स्टेशन, कार्यालय और कालेजों तक पहुंच सकें। परिवहन मंत्री ने कहा कि नए रिहायशी इलाकों और बाहरी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सहूलियत को देखकर ये ये रूट बनाए गए हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को अपने घर के पास से ही मेट्रो स्टेशन, बड़े बस अड्डों और कार्यस्थलों तक जाने के लिए सीधा साधन मिल सके।

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पहाड़गंज में पकड़ा हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट, 4 महिलाएं रेस्क्यू और संचालक गिरफ्तार

नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का नबी करीम थाना पुलिस की टीम ने भंडफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान चार महिलाओं को रेस्क्यू किया और सेक्स रैकेट संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान लक्ष्मी नगर के शाहरुख के रूप में हुई है। इसके अलावा मकान मालिक द्वारका के हरिकिशन उर्फ राजू चैंपियन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मध्य जिला उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, 11 जून की शाम करीब 7:30 बजे नबी करीम पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़गंज के कुतुब रोड स्थित सरन बिल्डिंग में अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है।

NOTICE

It is informed to the general public that I, KAUSHALYA RANI KOIRI, D.O.B.-11-08-1992, W/o - LATE CHINE LAL KOIRI, resident at Vill. - Kalamagura, P.O.- Kalamagura, P.S.- Ratabari, Dist.- Sribhumi, Assam, declare that my actual and correct name is "KAUSHALYA RANI KOIRI" and which has been correctly recorded in all my relevant documents but inadvertently in my Aadhaar Card vide No. 9942 1178 8373, Voter ID Card vide No. HQV0524777 and my PAN Card vide No. FLDPK3859J wherein my name has been wrongly recorded as "KAUSHALAYA RANI KOIRI" instead of "KAUSHALYA RANI KOIRI" In future I will be known as above said name.

बिल्कुल बर्दाश्त नहीं...ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर किसे दी सीधी चेतावनी

● होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने चल रही बातचीत के बारे में गलत जानकारी लीक की है और कहा कि तेहरान के सार्वजनिक बयानों में उन शर्तों का ज़िक्र नहीं है जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी।

● ट्रंप ने लिखा, ईरान ने 'फेक न्यूज़' को जो शर्तें बताई हैं, उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है। पर ईरानी हमले स्वीकार्य नहीं', बोले र राष्ट्रपति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान पर आरोप लगाया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश की। इस कथित घटना का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा ल रात होर्मुज जलडमरूमध्य से निकल रहे भारतीय जहाजों पर उनका ड्रोन हमला पूरी तरह नाकाम रहा और यह हरकत बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया और न ही यह बताया कि वे किन जहाजों की बात कर रहे थे। खबर लिखे जाने तक ईरानी अधिकारियों ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इस इलाके में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियानों में दर्जनों भारतीय नाविकों वाले 3 तेल टैंकर फंस गए हैं। 8 जून को अमेरिकी सेना ने पलाऊ के झंडे वाले टैंकर 'मैरीवेक्स' को बेकार कर दिया, जिस पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया।

दो दिन बाद, पलाऊ के झंडे वाले एक और टैंकर, 'सेटेबेलो' पर अमेरिकी हमला हुआ। इस जहाज़ पर 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से तीन की हमले में मौत हो गई। एक तीसरे टैंकर, 'जलवीर' पर भी हमला हुआ, जो गिनी-बिसाऊ के झंडे के साथ चल रहा था और जिस पर 20 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने चल रही बातचीत के बारे में गलत जानकारी लीक की है और कहा कि तेहरान के सार्वजनिक बयानों में उन शर्तों का ज़िक्र नहीं है जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने 'फेक न्यूज़' को जो शर्तें बताई हैं, उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने संभावित समझौते के बारे में ईरान की टिप्पणियों की भी आलोचना की और कहा कि उनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है और तेहरान पर ईमानदारी से बातचीत न करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए अपना संदेश खत्म किया और कहा, 'उन्हें जल्द से जल्द अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए!

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पी.वी. सिंधु का तूफानी खेल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को मात्र 27 मिनट तक चले एकतरफा मुकाबले में सीधे गेमों में 21-6, 21-9 से पराजित किया। सिंधु ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और आसानी से अंतिम चार में जगह पक्की कर ली।

सेमीफाइनल में सिंधु का सामना जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने भारतीय किशोरी तन्वी शर्मा के शानदार अभियान का अंत करते हुए उन्हें 21-14, 21-14 से हराया। यह मुकाबला 32 मिनट तक चला। सिंधू और यामागुची के बीच अब तक हुए मुकाबलों के आंकड़ों में भारतीय स्टार का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेले गए 28 मुकाबलों में सिंधू ने 15 जबकि यामागुची ने 13 जीत दर्ज की हैं। सिंधू के लिए यह सेमीफाइनल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सत्र में उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वह बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर पर लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को समाप्त करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ लय हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। सिंधू को दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद से अपने अगले खिताब का इंतजार है। इससे पहले सिंधू ने प्री-क्वार्टर फाइनल में हमवतन ईशारानी बरुआ को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी। पुरूष युगल में भारत के हरिहरन अम्साकरूनन और एम आर अर्जुन क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपै के चेन चेंग कुआन और लियू कुआंग हेंग से 19 . 21, 9 . 16 से पिछड़ने के बाद बाहर हा गए।

नोएडा में हाउस लिस्टिंग गणना 80% पर अटकी, धीमी प्रगति पर 30 प्रगणकों को नोटिस

नोएडा। प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव एसपी गोयल से फटकार लगने के बावजूद शुक्रवार तक नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग ब्लाक (एचएलबी) की गणना महज 80 प्रतिशत ही हो पाई है। शेष 20 प्रतिशत आनलाइन गणना भी रविवार तक पूरी करने का दावा किया गया है। विशेष बात ये है कि एचएलबी होने के बाद सोमवार से प्राधिकरण में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा आनलाइन डाटा को रिफाइन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कम जानकारी देने, ताला बंद मकान, सहयोग न करने वाले व्यक्ति, अनुपस्थित मतदाता या फिर भ्रामक सूचना देने वाले लोगों का डेटा तैयार कर दोबारा सत्यापन का काम होगा। धीमी गति से काम करने वाले 30 प्रगणकों को नोटिस जारी भी किए हैं। भारसाधन (चार्ज) अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि मकानों की आनलाइन गणना करने में प्राधिकरण व अन्य विभागों के 2100 स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने 12 जून तक 80 प्रतिशत मकानों की गणना कर ली है।

प्रशिक्षित एएसआई रेडियो तकनीशियन एवं आरक्षियों की पासिंग आउट परेड संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस अकादमी, झरोदा कलां में प्रशिक्षित सहायक उपनिरीक्षक रेडियो तकनीशियन और आरक्षियों के लिए पासिंग आउट एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 85 प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिल्ली पुलिस बल में अपनी सेवाएं देने के लिए कदम बढ़ाया। इनमें 37 सहायक उपनिरीक्षक रेडियो तकनीशियन जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, तथा 48 आरक्षी जिनमें 10 महिला आरक्षी शामिल हैं, ने प्रशिक्षण पूर्ण किया। समारोह में दिल्ली पुलिस अकादमी के उपनिदेशक राजबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया तथा शपथ ग्रहण कर निष्ठा एवं समर्पण के साथ सेवा करने का संकल्प लिया।

प्रशिक्षण के दौरान सहायक उपनिरीक्षकों रेडियो तकनीशियन को वायरलेस संचार प्रणाली के संचालन, वायरलेस उपकरणों की मरम्मत, नेटवर्क स्थापित करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा सभी प्रशिक्षुओं को पुलिस प्रक्रिया, आपराधिक कानून, अपराध विज्ञान, साइबर अपराध एवं फोरेंसिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान की गई। शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत निहत्थे मुकाबले, हथियार संचालन, फायरिंग, आतंकवाद निरोधक उपायों, योग, खेलकूद तथा व्यायाम जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। वहीं आरक्षियों को आपदा प्रबंधन, हथियार संचालन, कमांडो रणनीति, क्षेत्रीय संचालन तथा छापेमारी एवं घात लगाकर कार्रवाई करने जैसी महत्वपूर्ण विधाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। सहायक उपनिरीक्षक रेडियो तकनीशियन वर्ग में नवीन कुमार ने सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण प्रशिक्षु तथा इनडोर प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नीरज कुमार आउटडोर प्रशिक्षण में प्रथम रहे। आरक्षी वर्ग में महिला आरक्षी श्रुति मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण प्रशिक्षु, इनडोर तथा आउटडोर प्रशिक्षण की तीनों ट्रॉफियां अपने नाम कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। समारोह को संबोधित करते हुए आउटडोर प्रशिक्षण के सहायक निदेशक प्रभु दयाल ने प्रशिक्षुओं को बधाई दी और कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उनमें अनुशासन, टीम भावना और जनसेवा के मूल्यों का विकास

किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए प्रशिक्षुओं की विविधता दिल्ली पुलिस की शक्ति को और मजबूत बनाती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को शपथ भी दिलाई। मुख्य अतिथि राजबीर सिंह ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस में वायरलेस संचार व्यवस्था और आरक्षी बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में निर्बाध संचार व्यवस्था और आरक्षियों की त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की कि वे अपने आचरण, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के माध्यम से दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेंगे।समारोह में प्रशिक्षुओं के परिजन, दिल्ली पुलिस अकादमी के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समारोह का समापन प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हुआ।

तीन अलग-अलग हीरोइनों के साथ शूट हुआ था 34 साल पुराना ये गाना, सेट पर बदतमीजी कर रहे थे लोग

नई दिल्ली। आमिर खान की फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' को आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। फैन्स के बीच आज भी इसकी दीवानगी देखने को मिलती है। रिलीज के लगभग तीन दशक बाद भी इसका गाना 'पहला नशा' लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस गाने को बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। हाल ही में, कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने इस गाने के बनने से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर कीं।

अलग-अलग हीरोइनों के साथ हुआ शूट

फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्टर्स वेदांग रैना और शरवरी के साथ बातचीत करते हुए इस गाने से जुड़ी शूटिंग के दौरान की एक कहानी बताई। फराह ने कहा, 'हमारे पास न तो मॉनिटर थे और न ही माइक्रोफोन; हमने यह गाना 1990 में शूट किया था और फिल्म 1992 में आई थी। मैंने तीन अलग-अलग हीरोइनों के साथ यह गाना तीन बार शूट किया। हीरोइनें बदलती रहीं और आखिर में आयशा जुल्का आईं, जिनके साथ हमने जनवरी 1992 में शूटिंग की।'

सेट पर बदतमीजी कर रहे थे लोग

इससे पहले, 'जस्ट टू फिल्मी' के साथ बातचीत में आमिर खान ने बताया था कि फिल्म की कास्ट अलग थी और बाद में उसे बदल दिया गया था। इसलिए फिल्म की शूटिंग दोबारा की गई। उन्होंने आगे बताया कि मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। फिल्म में कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो सेट पर बहुत बदतमीजी करते थे। फराह ने कहा, 'वहां चार एक्टर्स थे और वे बहुत बदतमीज थे। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे हमें बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने मंसूर से कहा, 'अगर हम फिल्म का 80 परसेंट हिस्सा दोबारा शूट कर रहे हैं, तो इन चारों को भी हटा देते हैं और पूरी फिल्म ही दोबारा शूट करते हैं। मैं उन्हें दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता।'

क्यों दोबारा करनी पड़ी शूटिंग

आमिर ने बताया, 'फिल्म की शूटिंग दो बार हुई। हमने ऊटी और कोडाइकनाल में 60-70 दिनों तक शूटिंग की। हम वापस आए और दो महीने बाद मंसूर ने मुझे फोन करके कहा, 'देविका का किरदार ठीक नहीं लग रहा है।' उस समय देविका का रोल एक दूसरी एक्ट्रेस कर रही थीं। वह बहुत अच्छी लड़की और बेहतरीन एक्ट्रेस थीं, लेकिन मंसूर को लगा कि उनमें वह स्वाभाविक घमंड नहीं था जिसकी उस रोल के लिए जरूरत थी।' इसके बाद इसमें पूजा बेदी की एंट्री हुई और उनका पार्ट दोबारा शूट हुआ। फिल्म में दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, आयशा जुल्का, कुलभूषण खरबंदा, इमरान खान और किरण जावेरी भी थे।

दिल्ली मेट्रो की तरह NCR की नई लाइफलाइन बनेगी नोएडा की ई-सिटी बस सेवा, जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान

नोएडा। दिल्ली मेट्रो की तरह एनसीआर की लाइफ लाइन नोएडा की ई सिटी बस सेवा बनेंगी, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने ई सिटी बस की सुविधा को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही नहीं, बल्कि बाटेनिकल गार्डन (डीएमआरसी की ब्लू व मैजेंटा मेट्रो लाइन), दिल्ली (अक्षरधाम व आनंद विहार), गाजियाबाद (नया बस अड्डा व आरआरसीएस), ग्रेटर नोएडा के परी चौक, ग्रेनो वेस्ट जोड़ कर रूट प्लान तैयार किया। इस रूट पर 15 जून तक 110 ई सिटी बस का संचालन होगा, मांग बढ़ने पर 500 बसों का संचालन किया गया जाएगा। इस सेवा से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर के लोग ही नहीं, बल्कि मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम तक से आने जाने वालों को आसानी से ई सिटी बस के रूप में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

कप्तानी मिलने के बाद श्रेयस अय्यर ने मुंबई के वर्ली में लिया लग्जरी अपार्टमेंट, किराया जानकर उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली। हाल ही में श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई। अब श्रेयस अय्यर ने मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है। इस अपार्टमेंट का शुरुआती मंथली किराया 18.50 लाख रुपये है। इस डील और इसकी जानकारी 'स्क्वायर यार्ड्स' ने 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन' (IGR) की वेबसाइट पर जारी की है। वर्ली के 'आर्टेसिया' में स्थित यह अपार्टमेंट 3,875 वर्ग फीट में फैला है। इसमें चार पार्किंग स्पेस हैं। अय्यर ने तीन साल की लीज साइन की है। उन्होंने 1.84 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी, 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 74 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान किया है। एग्रीमेंट के अनुसार, किराया जो शुरू में 18.50 लाख रुपये प्रति माह है, वह दूसरे साल में लगभग 7% बढ़कर 19.79 लाख रुपये हो जाएगा। तीसरे साल में यह फिर से लगभग 7% बढ़कर 21.18 लाख रुपये हो जाएगा। इस तरह पूरे तीन साल के समय के लिए अय्यर को कुल 7.14 करोड़ रुपये किराया देना होगा।

आयलैंड से होंगे 2 टी20

30 महीने तक टी20 इंटरनेशनल नहीं

खेलने वाले श्रेयस अय्यर को हाल ही में सूर्यकुमार यादव की जगह भारतीय टी20 टीम की कमान दी गई। आयलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वह कप्तानी करते नजर आएंगे। 3 दिसंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में श्रेयस ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था।

51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले

श्रेयस ने अपने करियर में अब तक 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान 47 पारियों में उन्होंने 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में अय्यर ने 8 अर्धशतक लगाए हैं। 74 रन इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट स्कोर है। श्रेयस अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा।

रक्त दान सबसे बड़ा दान है रक्तदाता पुलिस मुख्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस के कल्याण प्रभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष पुलिस आयुक्त सतर्कता, कल्याण एवं अनुज्ञापन अतुल कटियार के मार्गदर्शन में तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों से जुड़े 82 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। शिविर के दौरान पुलिसकर्मियों में उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए इस सामाजिक अभियान को सफल बनाया।इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं, शल्य चिकित्सा, गंभीर बीमारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकती है। ऐसे में नियमित रक्तदान समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अधिकारियों ने यह भी कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें इस नेक कार्य के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, बल्कि विभिन्न सामाजिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी सक्रिय रूप से निभा रही है।दिल्ली पुलिस के कल्याण प्रभाग ने रक्तदान करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की

सराहना करते हुए शिविर को सफल बनाने में सहयोग देने वाले एम्स के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने रक्तदाताओं के इस योगदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलें सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करती हैं।पुलिस मुख्यालय में आयोजित यह रक्तदान शिविर दिल्ली पुलिस की जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया।

डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर ऑफिस, फरीदकोट

● 15 जून को पंजाब के गवर्नर फरीदकोट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करेंगे

● डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने तैयारियों का रिव्यू किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

फरीदकोट पंजाब के गवर्नर, गुलाब चंद कटारिया, 15 जून को फरीदकोट के अपने दौरे के दौरान रेड क्रॉस भवन में बनाए गए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करेंगे और फिर कल्चरल सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल में जिले के लोगों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट, श्री राहुल चाबा ने आज प्रोग्राम की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग में दी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर सन फाउंडेशन चलाएगा। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में युवाओं को सात अलग-अलग स्किल्स की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, ट्रेनी को नौकरी के मौके देने की भी कोशिश की जाएगी, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों

को गवर्नर के दौरे की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और प्रोग्राम को आसानी से आयोजित करने के लिए तालमेल से काम करने के निर्देश दिए।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इसके बाद गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया सरकारी बृजिंदरा कॉलेज में बने एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का दौरा करेंगे और वहां खिलाड़ियों से मिलेंगे और उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज) श्री संदीप मल्होत्रा, एसडीएम फरीदकोट श्री पुनीत शर्मा, एसडीएम कोटकपूरा राजिंदर सिंह, एस.डी.एम जैतो श्री विक्रमजीत, एक्स. वाटर सप्लाई शमिंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम अंजना कौंसल, एक्स. पीडब्लू .डी. नवजीत सिंह बराड़, डीएफएससी गुरजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बलजिंदर सिंह, एमसी म्युनिसिपल काउंसिल फरीदकोट श्री अमरींत लाल के अलावा अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

नोएडा एयरपोर्ट से रियल एस्टेट में बूम, 3 लाख रुपये बीघा की जमीन 80 लाख पहुंची; प्रॉपर्टी के दाम 4 गुना बढ़े

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के साथ आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट को नई ऊर्जा दी है। औद्योगिक निवेश, सेवा क्षेत्र के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। रियल एस्टेट कारोबार में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमिका का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नोएडा से लेकर जेवर तक रियल एस्टेट की कीमतों से आठ से 10 प्रतिशत तक वृद्धि पिछले चार से पांच साल के दौरान दर्ज हुई है। प्राधिकरणों को भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने संभावनाओं की नई उड़ान दी है। औद्योगिक निवेश के लिए जमीनों की मांग बढ़ी है। प्राधिकरणों की आवंटन दरों में वृद्धि से राजस्व का ग्राफ ऊंचा हुआ है। सेवा क्षेत्र और उद्योगों ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। गौतमबुद्ध नगर जैसे औद्योगिक जिले का हिस्सा होने के बावजूद जेवर क्षेत्र की पिछड़े क्षेत्र में गिनती थी, लेकिन जैसे-जैसे फाइलों में बंद पड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुगबुगाहटें बढ़ीं और केंद्र व राज्यों के बीच फाइलों दौड़ने ली, इसका असर क्षेत्र में भी नजर आने लगा।

ड्रग्स के खिलाफ जंग, ड्रग्स के खिलाफ डटकर खड़े होने की अपील की

● एंटी-ड्रग प्रोग्राम के दौरान, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने युवाओं से ड्रग्स के खिलाफ डटकर खड़े होने की अपील की।

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग आगे आए ताकि एक रंगीन पंजाब बनाया जा सके।

अमृतसर पंजाब सरकार द्वारा ड्रग्स को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को और असरदार बनाने के मकसद से, ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत आज जंडियाला गुरु में एक एंटी-ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर, पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ की लीडरशिप में गांव के सरपंचों, यूथ क्लबों, यूनियनों के नुमाइंदों और डिफेंस कमेटियों के सदस्यों के साथ एक खास मीटिंग भी हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार ड्रग्स को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और इस अभियान को लोगों का आंदोलन बनाने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश और पंजाब का भविष्य हैं और उन्हें ड्रग्स से दूर रखना हम सबकी साझी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ड्रग्स के खिलाफ डटकर खड़े हों और अपने गांवों और इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ें, तो पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर ने सरपंचों, यूनियनों और डिफेंस कमेटियों के सदस्यों से अपील की कि वे अपने-अपने इलाकों में एंटी-ड्रग एक्टिविटीज को तेज करें, युवाओं को स्पोर्ट्स, एजुकेशन और सोशल वर्क से जोड़ें और लोगों को ड्रग्स के बुरे असर के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जंग कैंपेन के तहत अब तक 60 हजार ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और 90 हजार से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स का सरकार ने डी-एडिक्शन सेंटर्स में फ्री इलाज किया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में ई-रिक्शा चलाए गए हैं जिनमें एक कंप्लेंट बॉक्स भी लगाया गया है जिसमें लोग बिना अपनी पहचान बताए ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट बॉक्स में जिस भी ड्रग पेडलर की जानकारी दी जाएगी, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मीटिंग को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष श्री गुरप्रताप सिंह संधू ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम को घर-घर तक पहुंचाया गया है और इसे खत्म करके ही पंजाब को फिर से रंगीन पंजाब बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस मुहिम के अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति मोर्चा के सभी वॉलंटियर राज्य को ड्रग फ्री बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मौके पर एसडीएम मैडम

अलका कालिया ने कहा कि लोगों के सहयोग से ही राज्य को ड्रग फ्री बनाया जा सकता है, अगर लोग सहयोग करेंगे तो और भी अच्छे नतीजे सामने आएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जंडियाला गुरु के डीएसपी श्री बलजीत सिंह ने कहा कि अगर आपके गांव में कोई भी ड्रग्स बेचता है तो मुझे सीधे इसकी जानकारी दें, किसी भी ड्रग तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर मौजूद गांवों के प्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भी ड्रग्स को खत्म करने के लिए हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया और पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए मिलकर कोशिश करने का संकल्प लिया। इस मीटिंग में नशा मुक्ति मोर्चा ग्रामीण के प्रेसिडेंट श्री कुलदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट निरवाल सिंह, काउंसलर सतिंदर सिंह, काउंसलर राज कुमार मल्होत्रा, बीडीपीओ श्री मलकीत सिंह, चेयरमैन गुरविंदर सिंह, सूबेदार शनाख सिंह, ब्लॉक प्रेसिडेंट केवल सिंह, सरपंच अमरीक सिंह, तहसीलदार अकविंदर कौर, एस.सी विंग के हल्का इंचार्ज मनजीत सिंह, शमशेर सिंह, अजयबीर सिंह, मौला सिंह के अलावा बड़ी संख्या में वॉलंटियर, डिफेंस कमेटियों के मेंबर और सरपंच मौजूद थे।